लक्ष्य : केंद्र से भुगतान में विलंब के कारण बाधित रहा काम

दैनिक जागरण 06-01-15

जातीय जनगणना की अंतिम सूची 15 तक होगी प्रकाशित

राज्य ब्यूरो, पटना : ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना की अंतिम सूची के प्रकाशन का लक्ष्य 15 जनवरी निर्धारित है। 14 जिलों की अंतिम सूची तैयार हो चुकी है। शेष 24 जिलों की 15 से पहले तैयार हो जाएगी। बतातें चलें कि केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर सूची 31 मार्च तक प्रकाशित नहीं की गई तो राज्य को केंद्रीय सहायता की राशि रोक दी जाएगी।

मिश्रा ने कहा कि इस जनगणना के सफल एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन की दृष्टि से देश के कुछेक बड़े राज्यों में बिहार शामिल है। प्रारूप सूची प्रकाशित की जा चुकी है मगर इसके लिए केंद्र सरकार ने मात्र 10 फीसद ही राशि दी है। 13 करोड़ रुपये बकाया हैं। इसी जनगणना के आधार पर बिहार में खाद्य सुरक्षा कानून लागू कर लाभान्वितों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि अनेक आकस्मिक व्यवधानों से विभाग को जूझना पड़ा है। भारत सरकार द्वारा इस जनगणना के लिए नामित एजेंसी ईसीआइएल द्वारा वेंडरों को भुगतान नहीं किए जाने के कारण काफी समय तक कार्य बाधित रहा है। अंततः राज्य सरकार ने पहल की और राज्य सरकार द्वारा ईसीआइएल को 24 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए। दावा एवं आपत्ति चरण का कार्य भी ईसीआइएल द्वारा किया जाना था, परन्तु वह उसे भी ससमय पूरा नहीं कर सका।

- 14 जिलों की सूची हो चुकी है तैयार, केंद्र से नहीं मिले हैं प्रारूप सूची के 13 करोड़

जिन जिलों की केंद्र को भेजी गई अंतिम सूची : नालंदा, पश्चिम चंपारण, बक्सर, शेखपुरा एवं बांका

बिहार देश का पहला राज्य है जहां सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना डाटा एवं राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी का डाटा एकीकृत कर प्रारूप सूची प्रकाशित की गई है।
-नीतीश मिश्रा, ग्रामीण विकास मंत्री

जिन जिलों की तैयार हो चुकी है अंतिम सूची : नालंदा, पश्चिम चंपारण, बक्सर, शेखपुरा, बांका, सीतामढ़ी, गया, समस्तीपुर, लखीसराय, जमुई, मधेपुरा, मधुबनी, रोहतास एवं मुंगेर